सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड

राज्य की चतुर्थ विधान सभा के वर्ष, 2020
के प्रथम सत्र में

श्रीमती बेबी रानी मौर्य

माननीय राज्यपाल, उत्तराखण्ड

का

अभिभाषण

भराड़ीसैंण, गैरसैंण (चमोली), मंगलवार, 03 मार्च, 2020 (फाल्गुन 13, शक सम्वत्, 1941)

उत्तराखण्ड राज्य के माननीय विधान सभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष एवं विधान सभा के माननीय सदस्यगण

मैं आप सभी महानुभावों का वर्ष, 2020 में विधान सभा के प्रथम सत्र में हार्दिक स्वागत करती हूँ और पर्वतराज हिमालय की गोद में बसे देव भूमि उत्तराखण्ड को एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने में दिये जा रहे सहयोग के लिए आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। आप के माध्यम से मैं प्रदेश के उत्तरोत्तर विकास की भी कामना करती हूँ। मुझे आशा है कि हम आगामी वर्ष में विकास की नई ऊँचाईयों को प्राप्त करेगें ताकि प्रत्येक क्षेत्र में हम नया आयाम स्थापित कर सकें।

मेरी सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस प्लान के अन्तर्गत मिशनमोड परियोजना (कोषागार कम्प्यूटराइजेशन) में आई.एफ.एम.एस. (IFMS) सॉफ्टवेयर को राज्य में लागू कर दिया गया है।

- लेखा परीक्षा का ऑनलाइन लेखा परीक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड मेनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर एन0आई0सी0 के माध्यम से विकसित किया गया है, जिस पर वर्तमान में शत–प्रतिशत कार्य ऑन लाइन किया जा रहा है।
- प्रदेश की समस्त जनता के लिए सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एवं रिन्यूवल व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गयी है।
- व्यापारी बीमा योजना के तहत विभाग द्वारा राज्य में पंजीकृत व्यवसायियों को व्यापारी दुर्घटना बीमा का लाभ प्रदान किये जाने हेतु बीमा योजना लाई गयी है।
- आम जनता की सुविधा हेतु विभागों की कार्यप्रणाली सरल बनाने की दिशा में विभाग की सम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु प्रवृत्त सर्किल दरों को ऑनलाइन प्रदर्शित किये जाने के सम्बन्ध में (G.I.S. Application) प्रवृत्त की गयी है।
- भूमि सम्बन्धी फर्जीवाडे को रोके जाने के लिये लेखपत्रों में भूमि की अवस्थिति के संज्ञान हेतु अंक्षाश एवं देशान्तर को लिखा जाना अनिवार्य किया गया है।
- भारत सरकार द्वारा प्रायोजित डिजिटल इण्डिया भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत निबन्धन कार्यालयों के कम्प्यूटराइजेशन, पुराने अभिलेखों के डिजिटाइजेशन तथा राजस्व कार्यालयों के अभिलेखों से जोड़े जाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया गतिमान है तथा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, के प्रभावी क्रियान्वयन के अन्तर्गत सम्बन्धित कार्य बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्यवाही सम्पादित कर ई–गवर्नेंस को करने में आसानी Ease of Doing Business, e-governance हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

राज्य के आर्थिक विकास में उद्योग क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य गठन के पश्चात् देश के उच्च विकास दर पाने वाले शीर्षस्थ राज्यों में उत्तराखण्ड राज्य सम्मिलित है और इसमें तीव्र औद्योगिक विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

- राज्य में अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने में सरकार द्वारा उद्योगों हेतु उपयुक्त वातावरण बनाने की दिशा में समुचित नीतियों के क्रियान्वयन, उच्च स्तरीय औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के सतत् विकास से इस क्षेत्र में राज्य ने विशेष सफलता अर्जित की है। उत्तराखण्ड देश के औद्योगिक मानचित्र में अपनी विशिष्ट उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रहा है।
- मेरी सरकार द्वारा 8 से अधिक क्षेत्रों के लिये मौजूदा नीतियों में संशोधन कर 10 नई प्रोत्साहनकारी नीतियॉ प्रख्यापित की गई हैं एवं 21270.97 करोड़ 457 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) की ग्राउडिंग की है।
- उद्योग क्षेत्र में 2641 इकाइयों की स्थापना के माध्यम से रू0 तीन हजार पाँच सौ चौबीस करोड़ का पूंजी विनियोजन तथा 57314 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।
- ''ईज ऑफ डुईंग बिजनेस'' में भारत सरकार द्वारा की गई रैंकिंग में राज्य 23वें स्थान से 9वें स्थान पर पहुंच गया है।
- राज्य की रैंकिंग पर्वतीय राज्यों में प्रथम स्थान पर है। निर्धारित कार्य बिन्दुओं पर और सजगता से कार्यवाही की गई है, जिससे कि राज्य की रैंकिंग में और सुधार किया जा सके।
- ''उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था" के अधीन कॉमन एप्लीकेशन फार्म (CAF) के माध्यम से ऑनलाइन 817 निवेश के प्रस्ताव स्वीकृत हुये, जिसमें दो हजार नौ सौ चौवालिस करोड़ का पूंजी विनियोजन तथा तेईस हजार नौ सौ सैंतीस लोगों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है।
- राज्य में निवेशक प्रोत्साहन सेन्टरों की स्थापना की गई है। विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की जा रही है। सिंगल विण्डो सिस्टम तथा स्टार्टअप नीति का क्रियान्वयन भी इन सेन्टरों के माध्यम से किया जा रहा है।
- नेशनल यूनिवर्सिटी आफ सिंगापुर के सहयोग से राज्य की एमएसएमई इकाइयों की उत्पादकता एवं दक्षता पर सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।
- क्लस्टर आधारित एप्रोच पर पर्वतीय क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु विनिर्माणक एवं सेवा क्षेत्र के उद्यमों के सफल संचालन हेतु 83 ग्रोथ सेन्टर के संचालक की प्रक्रिया गतिमान है, ग्रोथ सेन्टरों की स्थापना हेतु 1133.25 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

- स्टार्टअप नीति के अन्तर्गत अब तक राज्य से इन्वेस्ट इण्डिया में 66 स्टार्टअप मान्यता प्राप्त कर चुके हैं।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अधीन वित्तीय वर्ष में स्वीकृत 624 परियोजनाओं में 11.61 करोड़ का मार्जिन मनी संवितरित किया गया है।
- उद्यमिता एवं रोजगार की समग्र समीक्षा हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ''स्वरोजगार प्रोत्साहन एवं अनुश्रवण समिति'' का गठन किया गया है।
- "एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन योजना" 15 विकास खण्डों में संचालित की जा रही है। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रशिक्षित डिजाईनरों द्वारा शिल्पियों को नये डिजाईन एवं उत्पाद विकास को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (NITRA) के माध्यम से अल्मोड़ा में सेन्टर आफ एक्सीलेंस फॉर हिमालय रेशम की स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा एक एकड़ भूमि संस्थान हेतु उपलब्ध कराई गई है।
- सिडकुल के विभिन्न औद्योगिक आस्थानों में 22 इकाइयों को पचीस एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जिसमें रू0 आठ हजार दौ सौ एक्कीस करोड़ का पूंजी निवेश एवं एक हजार चार सौ पैंतालीस व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है।
- मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना के लिये **कलाम इन्सटीटयूट आफ हैल्थ टेक्नोलॉजी** के साथ एमओयू किया गया है।

मेरी सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क मार्ग से जोड़ने के दृष्टिगत 75 कि0मी0 ग्रामीण मोटर मार्गो का निर्माण किया गया है और तीन सौ उन्तीस किलोमीटर ग्रामीण मोटर मार्गो का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन मोटर मार्गों द्वारा दो सौ उनहत्तर ग्रामों को मुख्य मार्गो से जोड़ा जा चुका हैं, तथा लगभग एक लाख ग्रामवासी इससे लाभान्वित हो रहे हैं।

- ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाख सत्तर हजार दो सौ चौरानबे लाख रु0 की धनराशि से तेइस हजार भवन निर्माण कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं तथा आठ सौ सत्तावन भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों द्वारा निष्पादन अनुदान के रुप में वित्तीय वर्ष हेतु दो हजार एक सौ अट्ठावन लाख की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसे पात्र ग्राम पंचायतों को आवंटित किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु मूल अनुदान के रुप में पचास हजार आठ सौ एकत्तीस लाख राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों को आवंटित किया जाना लक्षित है।

- पंचायत प्रतिनिधियों के क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण, प्रादेशिक एवं प्रदेश से बाहर एक्सपोजर विजिट एवं प्रशिक्षण हेतु मूलभूत सुविधाओं के विकास तथा पंचायत भवनों के निर्माण हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।
- पंचायतों के लिए उत्तराखण्ड ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति लागू की गयी है। पंचायतों द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान तथा आय के स्वयं के स्त्रोतों/ उपभोक्ता शुल्क द्वारा ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन किया जाता रहा है।
- डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष में सभी 7954 ग्राम पंचायतों में खुली बैठकों के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजनाएं निर्मित की हैं 7949 योजनाएं प्लान प्लस पर अपलोड की जा चुकी हैं।
- नाना जी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के अन्तर्गत उत्कृष्ट पंचायत के रुप में वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत 'नेबी' विकास खण्ड कालसी को रु0 दस लाख का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- ई–पंचायत के अन्तर्गत पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त 11 साफ्टवेयरों में से राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों में ई–पंचायत के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष के लिए लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टीय का कार्य गतिमान है।

मेरी सरकार द्वारा पेराई सत्र 2019–20 हेतु गन्ना क्षेत्रफल चौरासी हजार हेक्टेयर प्राप्त कर लिया गया है जिसे आगामी पेराई सत्र में एक लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है।

- राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों हेतु रू0 दो सौ करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए राज्य की निजी क्षेत्र की चीनी मिलों हेतु रू0 एक सौ पचास करोड़ का सॉफ्ट लोन स्वीकृत किया गया है।
- गन्ना कृषकों के हितों के दृष्टिगत पेराई सत्र हेतु सरकार द्वारा गन्ना प्रजातियों हेतु रू0 तीन सौ सत्रह प्रति कुन्तल तथा सामान्य गन्ना प्रजातियों हेतु रू0 तीन सौ सत्ताइस प्रति कुन्तल की दर से निर्धारित की गयी है।
- गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र काशीपुर द्वारा गन्ना शोध के लिए विशेषज्ञ वैज्ञानिकों द्वारा राज्य स्तरीय, अन्तर्राज्यीय स्तरीय एवं ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण के माध्यम से गन्ना कृषकों एवं फील्ड कर्मचारियों को नवीनतम एवं आधुनिक तकनीकों से प्रशिक्षित किया जा रहा है।

मेरी सरकार ने वित्तीय वर्ष में वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 21508.39 हैक्टेयर क्षेत्र में एक करोड़ चौरानबे लाख पौधें रोपित किये गये हैं।

- मेरी सरकार बाघों के संरक्षण हेतु त्वरित गति से कार्य कर रही है। वर्ष 2006 की गणना में बाघों की संख्या एक सौ अठहत्तर आंकी गयी थी जो वर्तमान समय में बढकर चार सौ ब्यालीस हो गयी है एवं हाथियों की संख्या बढ़कर एक हजार आठ सौ छत्तीस हो गयी है।
- विगत दो वर्षों में लगभग चार करोड़ अड़तालिस लाख लीटर वर्षा जल संचय की संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में अड़तीस करोड़ लीटर संचय किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- मालसी डियर पार्क को देहरादून जू के रुप में विकसित किया गया है एवं हल्द्वानी में अन्तर्राष्ट्रीय जू कम सफारी विकसित किया जा रहा है।
- जायका परियोजना के अन्तर्गत वर्तमान तक बारह सौ कृषकों को उन्नत अखरोट के पाँच हजार पौधे उपलब्ध कराये जा चुके है।

आपदा की दृष्टि से उत्तराखण्ड राज्य एक संवेदनशील राज्य है। मेरी सरकार ने आपदा के कारण होने वाली क्षति के नियमित परिवीक्षण के लिए वेब आधारित ऑनलाइन रिपोर्टिंग व्यवस्था (सचेत) का विकास किया है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जन–जागरुकता, सरकारी योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु सामुदायिक रेडियों स्टेशनों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन नीति प्रख्यापित की है।

- दैवीय आपदाओं के दृष्टिगत आपदा प्रबन्ध तंत्र को मजबूत बनाये जाने हेतु महत्वपूर्ण भवनों की भूकम्प घातकता का आंकलन (Rapid Visual Screening) विधि से राज्य में एक सौ सात ऑटोमैटिक वैदर स्टेशन, पचीस सरफेस फील्ड आब्जरवेटरी, सोलह स्नोगेज एवं अट्ठाइस ऑटोमैटिक रैनगेज द्वारा तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई0एम0डी0) के तकनीकी सहयोग से आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना की है।
- राज्य में वर्तमान तक 22 गॉवों के 609 परिवारों के पुनर्वास हेतु रु0 एक हजार सात सौ चौरानबे लाख की धनराशि अवमुक्त की है।
- विश्व बैंक सहायतित परियोजना (यू0डी0आर0पी0–ए0एफ0) के अन्तर्गत पूर्णागिरी मन्दिर के भू–स्खलनग्रस्त ढलान की मरम्म्त (Slope Treatment) का कार्य प्रगति पर है एवं भवन निर्माण उपविधियों को उच्चीकृत किये जाने के उद्देश्य से विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत अध्ययन कार्य किया जा रहा है।

मेरी सरकार ने पशुपालन के क्षेत्र में पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से बछिया ही उत्पन्न किये जाने हेतु ऋषिकेश में सैक्स सीमेन उत्पादन प्रयोगशाला की स्थापना की है। मार्च 2019 से अब तक एक लाख सैक्स सोर्टेड सीमेन स्ट्रा का उत्पादन तथा दो हजार सात सौ पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किया जा चुका है।

- बद्री नसल की गायों की नस्ल सुधार हेतु पशुपालकों से फील्ड परफोरमेन्स रिकोर्डिंग के द्वारा चयनित पंचानबे उत्तम गायों का क्रय कर पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, नरियाल गांव (चम्पावत) में सम्वर्द्धन किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अन्तर्गत भेड़ों की नस्ल सुधार हेतु योजना स्वीकृत की गई है, जिसके सापेक्ष आस्ट्रेलिया से मैरिनो नस्ल के चालीस मेढ़े व दो सौ भेड़ें आयात किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत तेरह हजार एक सौ अस्सी ई0डब्ल्यू0एस0 आवासों की स्वीकृति केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गयी है। जिसमें से चार सौ चौसठ आवास मसूरी विकास प्राधिकरण द्वारा लाभार्थियों को आवंटित किये गये हैं।

- रूड़की में इन्द्रलोक आवासीय योजनान्तर्गत आवासहीन पाँच सौ अट्ठाइस परिवारों को केन्द्र सरकार द्वारा रू0 तीन सौ सोलह लाख की अनुदान राशि स्वीकृत कर अवमुक्त की है।
- भारत सरकार की मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 के अनुरूप देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश मैट्रोपोलिटन क्षेत्र हेतु व्यापक गतिशीलता योजना (C.M.P.) एवं वैकल्पिक विश्लेषण (alternative analysis) रिपोर्ट तैयार की गई है।
- हरिद्वार में हर की पैड़ी से चण्डी देवी मन्दिर तक तथा ऋषिकेश में उपयुक्त स्थान पर गंगा नदी के आर–पार रोप–वे के निर्माण हेतु फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जो कि शीघ्र तैयार कर ली जायेगी।

मेरी सरकार द्वारा राज्य के वन संसाधनों के ग्रीन लेखांकन तथा सतत् पर्यावरणीय निष्पादन सूचकांक की रिपोर्ट तैयार कर राज्य के वन संसाधनों के प्रवाह मूल्य, स्टॉक मूल्य एवं आर्थिक मूल्य को मौद्रिक रुप में मापा गया है। उत्तराखण्ड राज्य की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट 2019 तैयार करते हुए जनपदवार मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक, लैंगिक विकास सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक का आंकलन किया गया है।

- विभिन्न विभागों हेतु मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड युवा पेशेवर नीति, 2019 एवं अन्तःशिक्षुता नीति, 2019 का प्रख्यापन किया गया है।
- भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण आधारित योजना के लिए आंकड़ो का संग्रहण कर Geo portal तैयार किया जा रहा है।
- बाह्य सहायतित परियोजनाओं के लिये 90:10 की फन्डिग सुविधा प्राप्त करने के लिए वित्तीय वर्ष में पाँच योजनाओं के लिए भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जा रही है।

- राज्य में सतत् विकास लक्ष्य कार्यक्रम को अत्यधिक प्रभावी करने हेतु जिला स्तर पर सतत् विकास लक्ष्यों का सूचकांक तैयार किया जा रहा है।

मेरी सरकार द्वारा संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किये जाने एवं औद्योगिक वातावरण निर्माण हेतु प्रदेश में श्रम विषयक विभिन्न सुधार किये गये हैं।

- दुकानों व अधिष्ठान के पंजीकरण हेतु 24 घंटे ऑन–लाइन सुविधा प्रदान की गयी है तथा श्रमिक हितों को प्रभावित किये बिना प्रतिष्ठानों को वर्ष के सभी (365) दिन खोलने का प्रावधान किया गया है।
- महिला सशक्तिकरण एवं समानता के दृष्टिगत समस्त कारखानों में महिला कर्मकारों को रात्रि पाली में कार्य करने की व्यवस्था की गयी है।
- कारखानों के पंजीयन, नवीनीकरण, लाइसेंस स्वीकृति हेतु सरल व सुगम कार्य प्रणाली विकसित करने के लिए ऑन–लाइन व्यवस्था लागू की गयी है।
- प्रदेश में श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में 2013 की अपेक्षा लगभग 23 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए पुनरीक्षित वेतन जारी किया गया है।
- श्रमिकों को सुरक्षित, व्यवहारिक व भुगतान में पारदर्शिता लाये जाने के दृष्टिगत नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नकद या चैक या बैंक खाते में जमा करने हेतु प्रावधान किया गया है।
- व्यवसाय को सुगम बनाये जाने हेतु कारखानों के लाइसेन्स का नवीनीकरण अब वार्षिकी के स्थान पर दस वर्ष तक के लिए किये जाने का प्रावधान किया गया है।
- प्रदेश के समस्त कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु समस्त जनपदों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना से आच्छादित करने के लिए शेष सात पर्वतीय जिलों में भी योजना संचालित करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

मेरी सरकार द्वारा पूंजीगत कार्यो हेतु चालू वित्तीय वर्ष में 381 किमी0 लम्बाई में मार्गो का निर्माण, 697 किलोमीटर लम्बाई में मार्गो का पुनःनिर्माण तथा 20 सेतुओं का निर्माण करते हुए 47 ग्रामों को मुख्य मार्गो से जोड़ा जा चुका है।

- राज्य में विभिन्न श्रेणियों के बारह हजार तीन सौ अठहत्तर राजस्व ग्रामों को सड़क यातायात से जोड़ा गया है।
- अनुसूचित जाति उप योजना हेतु वित्तीय वर्ष में 23 किलोमीटर लम्बाई में नवनिर्माण, 09 किलोमीटर लम्बाई में पुनःनिर्माण तथा दो गॉवों को मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है। ट्राईबल सब प्लान में 21 किलोमीटर लम्बाई में नव निर्माण 06 किलोमीटर लम्बाई में पुनःनिर्माण एवं 2 गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है।

- दैवीय आपदा से एक हजार आठ सौ तेरह मार्ग एवं 26 सेतु (लकड़ी के लघु सेतुओं सहित) क्षतिग्रस्त हो गये थे, जिन्हें न्यूनतम अवधि में यातायात हेतु सुलभ किया गया है।
- देहरादून शहर में अजबपुर रेलवे क्रासिंग पर रोड़ ओवर ब्रिज आर0ओ0बी0 का निर्माण एवं आई.एस.बी.टी. के निकट दो लेन अतिरिक्त फ्लाई ओवर का निर्माण तथा जनपद हरिद्वार में डौसनी रेलवे क्रांसिंग के समीप दो लेन रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण कर यातायात हेतु उपलब्ध कराया गया है।
- ऑल वेदर रोड़ के अन्तर्गत प्रदेश में चारधाम परियोजना में छः सौ सोलह किलोमीटर लम्बाई के 36 कार्य निर्माणाधीन हैं।
- टिहरी में डोबरा–चांठी स्थान पर देश का सबसे लम्बा (लम्बाई 440 मीटर) सिंगल स्पान भारी वाहन झूला मोटर सेतु का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे अतिशीघ्र यातायात हेतु सुलभ कर दिया जायेगा।
- वित्तीय वर्ष में एक हजार पैंतालिस किमी0 का नवनिर्माण, एक हजार छत्तीस किलोमीटर लम्बाई में मार्गों का पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण एवं 87 सेतुओं का निर्माण करते हुए 147 ग्रामों को सड़क मार्गो से संयोजित किया जायेगा।

मेरी सरकार ने ग्राम स्तर पर गठित चार हजार एक सौ एकतालिस दुग्ध सहकारी समितियों के एक लाख पचपन हजार पैसठ दुग्ध उत्पादक सदस्यों द्वारा 1.85 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध उपार्जन किया जा रहा है, जिसके सापेक्ष दुग्ध उत्पादकों को रू 16.65 करोड़ का दुग्ध मूल्य भुगतान प्रतिमाह प्राप्त हो रहा है।

- प्रदेश में गठित 11 दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा 1.71 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध विक्रय किया जा रहा हैं।
- वित्तीय वर्ष 2019–20 में दुग्ध सहकारी समिति के लगभग 52 हजार दुग्ध उत्पादक सदस्यों को दुग्ध मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा रू0 4 प्रति लीटर की दर से दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करायी गई है। आगामी वित्तीय वर्ष में 54 हजार दुग्ध उत्पादक सदस्यों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
- प्रदेश में दुग्ध सहकारिताओं के सम्पूर्ण विकास एवं उनकी आवश्यकताओं हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्त पोषित रू0 चार सौ पैंतालिस करोड़ की योजना स्वीकृत की गयी है। योजनान्तर्गत मुख्यतः 03, 05 एवं 50 दुधारू पशुओं की इकाइयां स्थापित की जायेगी।
- दुग्ध सहकारी समिति सदस्यो को बीस हजार दुधारू पशुओं के क्रय हेतु ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था की गयी है। योजनान्तर्गत पाँच हजार दो सौ अस्सी लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना लक्षित है।

- पर्वतीय क्षेत्रों में चारे की कमी को दूर करने तथा दुधारू पशुओं के पोषण हेतु **"साईलेज एवं दुधारू पशु पोषण योजना"** प्रारम्भ की गयी है। योजनान्तर्गत दुग्ध सहकारी समिति सदस्यों को छः हजार पाँच सौ सड़सठ मैट्रिक टन मक्के का साईलेज, तिरासी हजार सत्तर किलोग्राम मिनिरल मिक्चर तथा आठ हजार सात सौ किलोग्राम प्रोबाइटिक्स 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
- साइलेज एवं पशुआहार के ढुलान व्यय के लिए सहायता प्रदान करने के उददेश्य से "पशुचारा परिवहन योजना" प्रारम्भ की गयी है। योजनान्तर्गत 6567 मैट्रिक टन साईलेज तथा 15840 मैट्रिक टन पशु आहार ढुलान हेतु सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।
- प्रदेश में स्थापित दुग्धशालाओं का उच्चीकरण एवं क्षमता विस्तार किया जायेगा। योजनान्तर्गत नैनीताल, देहरादून, चम्पावत एवं पिथौरागढ़ की वर्तमान दुग्ध उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि की जा रही है।
- केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं में अनुदान धनराशि तथा दुग्ध मूल्य भुगतान प्रत्यक्ष लाभ स्थानान्तरण (DBT) के माध्यम से किया जा रहा है।
- आंगनवाडी केन्द्रों में आ रहे तीन से छः वर्ष के एक लाख छाछठ हजार बालक एवं बालिकाओं को सप्ताह में दो दिन 100 मिलीलीटर दूध उपलब्ध कराने हेतु आंचल अमृत योजना के अन्तर्गत स्किम्ड मिल्क पाउडर उपलब्ध कराया जा रहा है।
- मिड डे मील योजना अन्तर्गत प्राईमरी तथा अपर प्राईमरी विद्यालयों में आ रहे सात लाख बालक एवं बालिकाओं को सप्ताह में एक दिन क्रमशः 100 मिलीलीटर व 150 मिलीलीटर दूध उपलब्ध कराये जाने हेतु मीठा सुगंधित फोर्टिफाईड स्किम्ड मिल्क पाउडर उपलब्ध कराया जा रहा है।

मेरी सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन के कार्यो को क्रियान्वित किये जाने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन,ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को श्रम रोजगार उपलब्ध कराने हेतु महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, ग्रामीण संयोजकता को पूर्ण करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बी.पी.एल. परिवारों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने एवं आवास उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण संचालित की गयी है।

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजनान्तर्गत सत्ताइस हजार चार सौ पचपन स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं पुनर्गठन कर संगठित किया गया है, जिन पर रू0 ग्यारह हजार एक सौ एक्यानबे लाख व्यय करते हुए गरीब महिलाओं के स्वावलम्बन हेतु कार्यवाही की गई है।

- सूक्ष्म एव लघु उद्योग (एम.एस.एम.ई.) में ग्रोथ सेन्टर योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा नौ ग्रोथ सेन्टरों में कुल दो सौ तेतीस लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायतों द्वारा रू0 अठाईस हजार पचास लाख व्यय किया गया है तथा अठ्ठासी लाख मानव दिवस सृजित कर अट्ठाइस हजार छः सौ सत्तावन स्थायी आर्थिक, सामाजिक परिसम्पत्तियों का निर्माण किया गया है।
- चार हजार छत्तीस परिवारों को 100 दिन का पूर्ण रोजगार प्रदान कर ग्यारह लाख परिवारों को जॉब कार्ड वितरित कर तथा तीन लाख श्रमिक परिवारों को श्रमरोजगार उपलब्ध कराया गया है।
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में चौदह हजार चार सौ चौरासी युवक–युवतियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। अब तक चौदह हजार दो सौ युवक–युवतियां के प्रशिक्षण का लक्ष्य नवीन चयनित 28 कार्यदायी संस्था को आवंटित किया जा चुका है, जिसके सापेक्ष 10 कार्यदायी संस्थाओं को प्रथम किस्त के रूप में रू0 11.12 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजनान्तर्गत राज्य में छः क्लस्टर है जिसमें से पाँच क्लस्टर में कार्य प्रगति पर है। एक अन्य क्लस्टर की डी0पी0आर0 तैयार की जा रही है। सोलह करोड़ पैंतीस लाख की धनराशि सी0जी0एफ0 (Critical Gap Funding) के रूप में व्यय की गई है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना–2011 के सर्वेक्षण के आधार पर आवास विहीन, कच्चे एवं जीर्णशीर्ण आवासों में रहने वाले निर्धारित पात्रता मान दण्डों के अनुसार जियो टैंगिंग के समय पात्र पाये गये 12666 परिवारों के सापेक्ष 12617 आवासों को स्वीकृति प्रदान की गयी है। एवं 12217 आवास पूर्ण किये गये हैं।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि रू0 उन्नीस हजार एक सौ एकतालिस लाख के सापेक्ष रू. चौदह हजार दो सौ चौरानबे लाख व्यय कर वर्ष में निर्माणाधीन 760 आवासों के सापेक्ष 641 आवास पूर्ण किये गये।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा 1872 बसावटों को जोड़ने हेतु स्वीकृत 2390 निर्माण कार्यों, 18249 के सापेक्ष 1274 कार्य, 11525 किलोमीटर पर निर्माण कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं जिन पर रू0 4458 करोड़ व्यय किये गये हैं तथा 1390 बसावटों को संयोजित किया गया है।

- प्रदेश में सड़क निर्माण हेतु ग्रीन टैक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। कार्यों की निविदाएं ई–टैण्डरिंग तथा भुगतान ई–पेमेंट के माध्यम से किये जा रहे हैं। पूर्ण मार्गों का अनुरक्षण प्रदर्शन आधारित रखरखाव अनुबन्ध (Performance Based Maintenance Contract) एवं महिला मंगलदलों के माध्यम से भी सामुदायिक अनुबन्ध (Community Contracting) के अन्तर्गत कराये जाने की पहल की गई है।
- सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के पाँच जनपदों चमोली, चम्पावत, उत्तरकाशी, ऊधमसिंहनगर तथा पिथौरागढ़ के 9 विकासखण्डों में कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उपलब्ध धनराशि रू0 39.80 करोड़ के सापेक्ष रू0 16.67 करोड़ व्यय कर ग्रामीण क्षेत्रों में 181 स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण किया गया है।
- एकीकृत आजीविका सुधार (आईफैड) परियोजना का संचालन चयनित 44 विकासखण्डों में किया जा रहा है। तेरह हजार आठ सौ एक्वानबे उत्पादक समूहों के माध्यम से एक लाख उन्तीस हजार अडसठ परिवारों को मुख्यतः कृषि आधारित गतिविधियों में उत्पादन बढाने हेतु सहयोग दिया गया है।
- किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से एक सौ छियासी फार्म मशीनरी बैंक एवं बारह कस्टम हायरिग सेन्टर स्थापित किये गये हैं।
- कृषि उपकरणों के उपयोग से कृषि कार्य में महिला श्रम व अन्य श्रम लागत में 50 से 60 प्रतिशत की कमी हुई हैं।
- मेरा गांव मेरी सड़क योजना के अन्तर्गत तीन सौ छप्पन योजनायें स्वीकृत की गयी, जिसके सापेक्ष 330 सड़कें पूर्ण करते हुए 301 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है।

मेरी सरकार **द्वारा** उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य कार्मिकों के आंवटन का कार्य भारत सरकार द्वारा गठित राज्य परामर्शीय समिति के स्तर से पूर्ण कर लिया गया है।

मेरी सरकार महिला सशक्तिकरण एवं बाल **विकास** हेतु प्रतिबद्ध है। गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु "**प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना**" के अन्तर्गत एक लाख नौ सौ सत्रह लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

- "नंदा गौरा योजना" के अन्तर्गत चौबीस हजार नौ सौ पचपन लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।
- मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान के अन्तर्गत राज्य के चिन्हित कुपोषित व अतिकुपोषित बच्चों के लिए स्थानीय खाद्यान्नों पर आधारित पूरक पोषाहार की सामग्री तैयार की जा रही है, जिसे ऊर्जा नाम दिया गया है।

- राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार के अन्तर्गत राज्य की कुल अठारह महिला एवं किशोरियों को सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र एवं एक्कीस हजार रूपये की धनराशि दी गयी है।
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अन्तर्गत 'राष्ट्रीय बालिका दिवस' के सुअवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जिला देहरादून को Effective Community Engagement कार्यों हेतु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- राज्य में मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना, राष्ट्रीय महिला हेल्प लाईन 181, निर्भया योजना, उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना एवं किशोरियों हेतु सैनेटरी नैपकिन की व्यवस्था, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना एवं आंगनबाड़ी कल्याण कोष का संचालन किया जा रहा है।
- मेधावी छात्राओं को पठन–पाठन में सहयोग हेतु मोबाइल उपलब्ध कराये गये हैं।
- प्रदेश में निराश्रित बच्चों की शिक्षा एवं भरण–पोषण हेतु खुला आश्रय गृह का संचालन किया जा रहा है। मानसिक एवं शारीरिक रूप से दिव्यांग महिलाओं का संरक्षण तथा चिकित्सा इत्यादि की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्‌देश्य से देहरादून में राजकीय नारी निकेतन का संचालन किया जा रहा है।
- प्रवर्तकता योजना में अनाथ/बेसहारा बच्चे जो विस्तारित कुटुम्ब के साथ रह रहे है, अशक्त तथा गम्भीर रोग से ग्रसित, सजायाफ्ता माता–पिता की सन्तान, विधवा/तलाकशुदा स्त्री परित्यकता, कुटुम्ब द्वारा परित्यक्त महिला के बालक/बालिकाओं को आर्थिक सहायता के रूप में शिक्षा तथा चिकित्सा हेतु दो हजार रूपये प्रतिमाह दिया जा रहा है।

मेरी सरकार द्वारा सात लाख वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगों, किसानों व परित्यक्त महिलाओं को ससमय पेंशन दी जा रही है।

- सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु उत्तराखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली बनायी गयी है।
- ऊधमसिंहनगर एवं देहरादून में मानसिक रूप से दिव्यांगों हेतु पुनर्वास गृह की स्थापना की प्रक्रिया गतिमान है और इस हेतु भूमि आवंटित कर दी गयी है।
- वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगजनों आदि की सहायता हेतु प्रदेश में 275 बहुउद्‌देशीय शिविरों का आयोजन किया गया है।
- भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना 'प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना'' (PMAGY) के कियान्वयन हेतु राज्य के 500 से अधिक जनसंख्या वाले ऐसे गॉवों को जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या हो ''आदर्श ग्राम'' बनाने हेतु 194 ग्रामों को चयनित किया गया है।

- पेंशन एवं छात्रवृत्ति योजना को पारदर्शी एवं समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन करने हेतु इन योजनाओं का संचालन ऑनलाइन और डी.बी.टी. के माध्यम से किया गया हैं।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे एक सौ चौदह प्रशिक्षणार्थियों को कैम्पस प्लेसमेन्ट के द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
- अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रशासनिक सेवा एंव अन्य प्रतियोगी परीक्षा हेतु निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है।
- अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सात सौ अठ्ठानबे लाख की धनराशि व्यय कर बाइस हजार एक्यानबे छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।
- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन योजनान्तर्गत तेईस करोड़ सत्तावन लाख की धनराशि व्यय कर दो हजार एक सौ चौहत्तर छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।
- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी में वित्तीय वर्ष में दो करोड़ ग्यारह लाख की धनराशि व्यय कर 396 छात्रों को लाभान्वित किया गया है।
- बाजपुर व खटीमा में एक–एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना का कार्य प्रस्तावित है।
- बुक्सा एवं राजी जनजाति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में सोलह लाख सत्तर हजार व्यय कर 351 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।
- अनुसूचित जनजातियों की पुत्रियों का विवाह योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में 744 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

मेरी सरकार द्वारा राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों का डाटा आर0सी0एम0एस0 में फीड किया गया है। राशन कार्डधारकों के सभी यूनिटों का आधार वेलिडेशन करते हुये सम्पूर्ण डाटा शुद्धीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

- पुराने बुकलेट राशन कार्ड के स्थान पर नवीन पी0वी0सी0 राशन कार्ड(वोटर आई0डी0 की भांति) QR कोड सहित प्रारम्भ कर दिये गये हैं।
- **डोर स्टेप डिलीवरी** के अन्तर्गत राज्य के तीन जनपदों देहरादून, हरिद्वार तथा नैनीताल एवं तीन ब्लॉकों सहसपुर, बहादराबाद, रामनगर में पॉयलट प्रोजेक्ट किया जा रहा है।
- **राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी** रूड़की नगरीय क्षेत्र को इन्ट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी के पॉयलेट प्रोजेक्ट हेतु चयनित किया गया है, जिसके अन्तर्गत लाभार्थियों को राज्य के किसी भी सस्ता गल्ला की दुकान से राशन प्राप्त हो सकेगा।

- राज्य के समस्त जनपदों की नौ हजार तीन सौ पाँच राशन की दुकानों में सिस्टम इन्टिग्रेटर (सी0एस0सी0 एस0पी0वी) के माध्यम से ऑटोमेट किये जाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। राशन की दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने का कार्य गतिमान है।
- गेहूँ खरीद हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर काश्तकारों को उनकी उपज का अधिक लाभ प्रदान करने हेतु बीस रूपये प्रति कुन्तल का अतिरिक्त बोनस दिया गया है।
- मूल्य समर्थन योजना अन्तर्गत धान का क्रय ई–खरीद सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन करते हुए भारत सरकार के राष्ट्रीय खरीद पोर्टल (National Procurement Portal) पर प्रदर्शित किया जा रहा है।
- भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को ऑयरन एवं आयोडीन की कमी को दूर किये जाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा ऊधमसिंह नगर के जसपुर ब्लॉक के चावल मिलर्स को राईस फोर्टिफिकेशन कर पायलेट योजना का निर्णय लिया है।

मेरी सरकार राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रख–रखाव तथा उन्नयन हेतु संगीत, नृत्य, नाटक, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कला आदि का विकास तथा इनका व्यापक प्रचार–प्रसार, पुरातात्विक स्थलों एवं स्मारकों का संरक्षण, सर्वेक्षण व अनुरक्षण, प्राचीन अभिलेखों एवं दुर्लभ पाण्डुलिपियों को संग्रहीत कर उनका संरक्षण तथा ऐतिहासिक धरोहर/पुरासम्पदा को सुरक्षित रखना आदि महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन किया जा रहा है।

- पौड़ी गढ़वाल के कोट ब्लॉक स्थित ग्राम फलस्वाड़ी में सीता माता मन्दिर को विकसित कर वीरांगना तीलू रौतेली के नाम पर वीरोंखाल में उनके शौर्य एवं संघर्ष से जुड़ी वर्णित घटनाओं को संग्रहीत किये जाने हेतु संग्रहालय स्थापित किया जायेगा।
- धार्मिक आस्था के महत्वपूर्ण केन्द्र प्रदेश के लगभग 100 वर्ष पुराने देवालयों, मन्दिरों, स्थलों एवं स्मारकों का वृहद् सर्वेक्षण कराकर उनके विकास हेतु 'विरासत की अंगीकार योजना' में लिया जायेगा।

मेरी सरकार उत्तराखण्ड निवास, नई दिल्ली को आधुनिक सुविधायुक्त बनाये जाने हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ कर रही है।

- भराड़ीसैण में मिनी सचिवालय के निर्माण के लिए भूमि का चिन्हीकरण कर लिया गया है।

मेरी सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। छात्र/छात्राओं के लिए अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत एक करोड़ की प्रोत्साहन धनराशि

के सापेक्ष प्राप्त बारह सौ आवेदनों में से चयनित 588 छात्राओं को अट्ठानबे लाख पंचानबे हजार की धनराशि वितरित की गयी है।

- प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित धनराशि 2700 लाख के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कुल 13 नये कार्यो हेतु 446.10 लाख की धनराशि स्वीकृत की है एवं 14 अन्य कार्यो की स्वीकृति की कार्यवाही गतिमान है।

मेरी सरकार जनता के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु सरकार की नीतियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी विभिन्न सेंवाओं के माध्यमों से जन–जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है।

- श्रमजीवी पत्रकारों एवं सक्रिय पत्रकारों को पत्रकार कल्याण कोष से आर्थिक सहायता दी जा रही है।
- असाध्य रोगों से पीड़ित पत्रकारों को उनके इलाज के लिए आर्थिक सहायता, मृत्यु होने की दशा में उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता के साथ–साथ आकस्मिकता की स्थिति में भी उनके आश्रितों को सहायता प्रदान की जा रही है।
- परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है।
- राज्य में फिल्मों की शूटिंग के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार कर फिल्म निर्माताओं की सुविधाओं के दृष्टिगत आकर्षक फिल्म नीति लागू की गई है।
- शूटिंग हेतु अनुमति सिंगल विन्डों के माध्यम से दी जा रही है।
- राज्य को 66 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अन्तर्गत Most Film- Friendly State का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

मेरी सरकार द्वारा जनवरी, 2020 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से पूर्व मतदाता सत्यापन कार्यक्रम (EVP) संचालित किया गया है।

- राज्य में शत–प्रतिशत मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र निर्मित कर उपलब्ध करा दिये गये है।

मेरी सरकार आयुष चिकित्सा पद्धति की उन्नति के लिए निरन्तर प्रयासरत है। राज्य के समस्त जनमानस को सस्ती, सुलभ एवं दुष्परिणाम रहित चिकित्सा पद्धति उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया जा रहा है।

- पिरान कलियर में यूनानी कॉलेज की स्थापना हेतु सरकार द्वारा दो करोड़ तथा आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चार करोड़ छियालिस लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।
- 50 शैय्यायुक्त राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना की जा रही है।
- राज्य की 12 हजार आशा एवं ए0एन0एम0 कार्यकर्ताओं को आयुष पद्धति से घरेलू उपचार आदि का मास्टर ट्रेनरों के द्वारा प्रशिक्षण दिये जाने की कार्यवाही गतिमान है। प्रथम चरण में चार हजार आशा एवं ए0एन0एम0 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है।
- राज्य के आठ उच्चीकृत चिकित्सालयों में योग के माध्यम से रोगियों का उपचार किया जा रहा है।
- स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत राज्य में संचालित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के पास उपलब्ध भूमि में हर्बल गार्डन विकसित किये जाने हेतु अधिकतम औषधीय पौधे विकसित किये जा रहे हैं।

मेरी सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, संयुक्त चिकित्सालयों एवं बेस चिकित्सालयों में होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना राजभवन में होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना व देहरादून में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

- राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के अंतर्गत स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित किये जाने हेतु 152 पदों का सृजन किया गया है।
- केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी एवं देहरादून में ट्रॉमा सेन्टर एवं बर्न सेन्टर स्थापित किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।
- ग्राम स्तर पर उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा कैंसर के प्रारम्भिक अवस्था में जॉच के लिए कार्यशील स्वास्थ्य उप केन्द्रों में हैल्थ एवं वैलनेस सैंटर स्थापित किये जा रहे हैं।
- आयुष्मान भारत योजना को और आगे बढाते हुए अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अंतर्गत 23 लाख परिवारों को पाँच लाख रूपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
- योजनान्तर्गत 34 लाख लोगों को गोल्डन कार्ड उपलब्ध करा दिये गये हैं।
- सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, अल्मोड़ा को शीघ्र प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

- राज्य में तीन नर्सिंग कॉलेज चम्पावत, बाजपुर एवं गुप्तकाशी में नर्सिंग कॉलेज के निर्माण की कार्यवाही गतिमान है।
- राज्य के तीन मेडिकल कॉलेजों में श्रीनगर, हल्द्वानी एवं देहरादून में पैरामेडिकल पाठयक्रम संचालन की कार्यवाही गतिमान है।
- चिकित्सकों के रिक्त पदों पर चयन की प्रकिया गतिमान है।

मेरी सरकार ने वित्तीय वर्ष में खनिजों से राजस्व प्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष एक सौ बहत्तर करोड़ का राजस्व अर्जित किया है।

- उपखनिज सोपस्टोन एवं सिलिका सैण्ड इत्यादि खनिज भण्डारों की खोज व उनका समुचित विकास किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।
- राजस्व वृद्धि तथा रोजगार के समुचित अवसर सृजित किये जाने के दृष्टिगत राजस्व एवं वन क्षेत्र में उपलब्ध अधिक से अधिक उपखनिज क्षेत्रों की खोज/चिन्हित करते हुये उनका आवंटन कराये जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है।

राज्य में पर्यटन के विकास हेतु सहस्त्रधारा हैलीपैड से श्री केदारनाथ दर्शन, हेमकुण्ड सहिब दर्शन हैली सेवाएं प्रारम्भ की गयी है।

- राज्य में तीन एयर फील्ड कनेक्टिविटी जौलीग्रान्ट, चिन्यालीसौड़ एवं गौचर में वायुयान सेवाएं प्रारम्भ की गयी हैं।
- उड़ान योजना के अन्तर्गत जन सामान्य को सस्ती दरों पर हेली सेवा प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।
- देहरादून से पिथौरागढ़ नैनीसैनी, तथा हिण्डन से पिथौरागढ़ एवं देहरादून से पंतनगर हेतु हवाई सेवा प्रारम्भ की गई है।

मेरी सरकार हिन्दी, उर्दू, पंजाबी एवं लोकभाषा एवं बोलियों के संवर्धन एवं विकास हेतु प्रयासरत है।

- स्वरचित कृतियों के लिए पुरस्कार योजना, शोध परियोजनाएं, हिन्दी, उर्दू एवं पंजाबी भाषा सम्मेलन आयोजित किये जा रहे हैं।

मेरी सरकार द्वारा डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकार्ड मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) के अन्तर्गत प्रदेश के 13 जनपदों में से दो पॉयलट जनपदों अल्मोड़ा एवं पौड़ी गढ़वाल में योजना के कार्यों कैडस्ट्रल मैप्स का डिजिटाईजेशन एवं तहसीलों में मॉर्डन रिकार्ड रूम (स्वयं का राजकीय भवन वाली तहसीलों में) की स्थापना सम्बन्धी कार्य पूर्ण करवाया गया है।

- भूलेख सॉफ्टवेयर को प्रदेशभर में पूर्ण रूप से संचालित करने की प्रक्रिया पूर्ण की गयी है।
- हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, चम्पावत व नैनीताल के 906 ग्रामों के सापेक्ष 426 ग्रामों में चकबन्दी का कार्य पूर्ण हो चुका है, 198 ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया गतिमान है।

विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में जारी एकीकृत रैंकिंग में उत्तराखण्ड राज्य देश के प्रथम तीन राज्यों में (गुजरात एवं कर्नाटक के साथ) सम्मिलित हैं।

- मेरी सरकार ने सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत 5 मेगावाट क्षमता तक की सौर परियोजनाओं का आवंटन राज्य के स्थायी निवासियों को पर्वतीय क्षेत्रों में अधिष्ठापित किये जाने हेतु आरक्षित किया है।
- राज्य में वनाग्नि को रोके जाने के उद्देश्य से वन विभाग के सहयोग से सरकार द्वारा प्रख्यापित पिरूल नीति–2018 के अन्तर्गत वर्तमान में 675 किलोवाट की परियोजनायें विभिन्न जनपदों में स्थापित किये जाने हेतु आवंटित की जा चुकी हैं।
- द्वितीय चरण में 17 परियोजनाओं के आवंटन की प्रक्रिया गतिमान है। इन परियोजनाओं से स्थानीय निवासियों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है।
- राज्य के निवासियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से समस्त विकासखण्डों में एल0ई0डी0 आधारित उपकरणों के निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- भारत सरकार द्वारा संचालित नवीन योजना किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान ''कुसुम'' योजनान्तर्गत सोलर पावर प्लाण्ट तथा सोलर पम्प स्थापित कराये जाने हेतु योजना का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से किया जा रहा है।
- राज्य के अन्तर्गत प्रत्येक जिलों के एक–एक ग्राम को ''ऊर्जा दक्ष ग्राम'' के रूप में विकसित कराये जाने का कार्य प्रगति पर है।
- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत 94 अविद्युतीकृत ग्रामों का शत–प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया गया है।
- एकीकृत ऊर्जा विकास योजना के अन्तर्गत (आईपीडीएस) देहरादून एवं हरिद्वार के सरकारी भवनों पर 17.99 करोड़ की लागत से सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किये जाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।
- हरिद्वार में विद्युत लाईनों को भूमिगत किये जाने का कार्य प्रगति पर है।

- राज्य में विद्युत उत्पादन हेतु नवीन परियोजनाओं के निर्माण की दिशा में 120 मेगावाट क्षमता की व्यासी जल विद्युत परियोजना, मद्महेश्वर, कालीगंगा–प्रथम एवं कालीगंगा–द्वितीय तथा सुरिनगाड़–द्वितीय) का निर्माण कार्य त्वरित गति से चल रहा है।
- राज्य में बढते विद्युत भार एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं की विद्युत पारेषण के दृष्टिगत पारेषण तंत्र को सुदृढ किया जा रहा है।
- मीटरिंग व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु इस वर्ष शत–प्रतिशत मीटर नई तकनीक पर आधारित ए0बी0टी0 मीटरों द्वारा बदले जाने का लक्ष्य है।

मेरी सरकार मादक पदार्थों के अनौषधीय उपयोग के निषिद्ध करने की दिशा में प्रयारत है। मद्यनिषेध की मूल अवधारणा को प्रमुखता प्रदान कर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का प्रभावी अनुश्रवण करते हुए मादक पदार्थों की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

- प्रदेश में औद्योगिक भांग की खेती हेतु निर्धारित शर्तों एवं मानकों पर अनुज्ञापन प्रदान किये जा रहे हैं, जिससे स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि हो रही है।

मेरी सरकार ग्रामीण रोजगार के दृष्टिगत मत्स्य पालन को प्रोत्साहित कर रही है।

- राज्य के प्रथम ट्राउट ब्रूड बैंक की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
- राज्य में मात्स्यिकी विकास गतिविधियों को सहकारिता के माध्यम से विस्तारित कर मत्स्य उत्पादन में आशातीत वृद्धि हेतु केन्द्रीय क्षेत्रक कृषक सहकारिता एकीकृत योजना के अन्तर्गत मत्स्य क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न परियोजनाओं के लिए एक सौ पैंसठ करोड़ रुपये की स्वीकृत की गयी है।
- योजना के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के बेहतरीन अवसर सृजित करने हेतु "ट्राउट फार्मिंग परियोजना" संचालित की जायेगी जिसके अन्तर्गत 1000 रेसवेजो का निर्माण किया जायेगा।
- योजना से लगभग दो हजार पाँच सौ प्रत्यक्ष एवं सात हजार पाँच सौ अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगें। एंग्लिग पर्यटन से रोजगार सृजन तथा मात्स्यिकी संरक्षण के प्रोत्साहन हेतु राज्य की नदियों में वर्तमान तक कुल 51 बीटों को स्थानीय समूहों को आंवटित किया गया है।
- मत्स्य पालकों हेतु किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था प्रारम्भ कर दी गयी है। मत्स्य प्रसंस्करण व्यवसाय को स्थापित किये जाने हेतु आठ मोबाइल फिश आउटलेट एवं चार ई–रिक्शा आधारित मोबाइल फिश स्टॉल प्रारम्भ किये गये है।

मेरी सरकार द्वारा नशे के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए विगत एक वर्ष में सत्रह करोड़ की अवैध ड्रग्स बरामद की गई।

- छात्रों में नशे के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए शिक्षकों, छात्रों, तथा अभिभावकों को शामिल करते हुए 1500 नशा विरोधी समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां छात्रों की नियमित मेडिकल जॉच तथा छात्रों तथा अभिभावकों में जागरूकता बढ़ाने का काम कर रही हैं।
- राज्य के 132 थानों में CCTV कैमरा लगाया जा चुका है, शेष 26 थानों में कार्यवाही अन्तिम चरण में हैं।

मेरी सरकार द्वारा राज्य परियोजनाओं, कार्यो के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु मुख्यमंत्री डेशबोर्ड की स्थापना सी0एम0 हैल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का समाधान त्वरित गति से किया जा रहा है।

- ड्रोन तकनीक के व्यापक प्रचार–प्रसार एवं राज्य के आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से राज्य स्तर पर पॉलिटेक्निक एवं इंजिनियरिंग के छात्र–छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क स्टेट वाईट एरिया नेट (SWAN) से लगभग 30 मुख्य विभाग आच्छादित किये जा चुके हैं। SWAN के अपग्रेडेशन के अन्तर्गत राज्य मुख्यालय सहित पाँच जनपद मुख्यालय तथा उनके तहसील एवं ब्लॉक मुख्यालय में स्वान उपकरणों के उच्चीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- राष्ट्रीय सूचना अवस्थापना (NII) की पायलट परियोजना के अन्तर्गत जनपद मुख्यालय, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, तहसील मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय, परिवहन कार्यालयों को सचिवालय स्तर तक विडियो कान्फ्रेसिंग सिस्टम के माध्यम से जोड़ने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- ई–डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से नागरिकों को 27 सरकारी सेवाएं आनलाइन प्रदान कर वर्तमान में ई–डिस्ट्रिक्ट 2.0 का नवीन संस्करण विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन करते हुए प्राकृतिक संसाधन आधारित आजीविका विकसित किये जाने का कार्य गतिमान है।
- प्राचानी गुफाओं को पर्यावरणीय पर्यटन (Eco-tourism circuit) के रूप में विकसित करने हेतु सर्वे कार्य पूर्ण कर यूसर्क द्वारा पाठ्यक्रम सामग्री निर्माण हेतु विषय विशेषज्ञों द्वारा ई–कन्टेन्ट के निर्माण हेतु व्याख्यान आयोजित किये जाने का कार्य गतिमान है।

- यूसर्क द्वारा दिव्यांगों हेतु **'दिव्यांग केन्द्र'** की स्थापना की गयी है जिसके अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

मेरी सरकार ने उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु गरीब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है।

- रूसा योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा दो विश्वविद्यालयों, दो मॉडल कॉलेज, एक व्यावसायिक कॉलेज तथा एक्कीस राजकीय महाविद्यालयों को अनुदान हेतु चयन किया गया है, जिसमें एक सौ सैंतीस करोड़ की धनराशि अनुमन्य की गयी है।

- राज्य के सभी महाविद्यालयो में यू0जी0सी0 के मानकानुसार प्राध्यापकों के पद सृजित किये जाने एवं तीन हजार से अधिक की छात्र संख्या वाले महाविद्यालयों में सभी प्रकार के विषयों एवं रोजगार परक पाठ्यक्रमों का संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

- आवासीय विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की मांग के दृष्टिगत भूमि आईटी इन्नोवेटर्स प्रा0लि0 के साथ डिजिटल मार्केटिंग विषय पाठ्यक्रम का संचालन पार्टनं मानसरोवर सोसाईटी के साथ किया जा रहा है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन रोकने के प्रयोजन से ग्रामीण क्षेत्रों के गांवों को कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा गोद लिया गया है जहॉ विश्वविद्यालय के पृथक–पृथक विभागों एवं राष्ट्रीय सेवा योजना एवं राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा गाँव में सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न परिसरों के छात्र–छात्राओं को बहुआयामी एवं परिष्कृत शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु esa Language Lab का गठन किया जा रहा है।

- पर्वतीय जड़ी बूटी के विकास हेतु विश्वविद्यालय में सेन्टर फार एक्सीलैंस ऑफ मेडिसनल प्लाण्ट एवं टैक्नोलॉजी की स्थापना की गई है।

मेरी सरकार द्वारा राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबों को पाठ्यक्रम में शत–प्रतिशत लागू किया गया है। इससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है।

- शासकीय विद्यालयों में छात्रों को नामांकित करने हेतु जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 'प्रवेशोत्सव' कार्यक्रम प्रारम्भ कर 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लास रूम के माध्यम से शिक्षण दिये जाने का लक्ष्य है।

- समस्त राजकीय प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय, पेयजल, कम्प्यूटर एवं समस्त छात्र–छात्राओं को बैठने हेतु फर्नीचर उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य 2022 तक रखा गया है।
- आपदा की दृष्टि से संवेदनशील विद्यालय भवनों का रेट्रोफिटिंग/पुनर्निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है।
- विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्वस्थ,मेधावी एवं प्रतिस्पर्धात्मक भावना के साथ सर्वांगीण विकास करने हेतु योग ओलम्पियाड का आयोजन किया गया।
- "राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम की गतिविधियों का विद्यार्थियों के जीवन कौशल पर प्रभाव" पर शोध कार्य किया जा रहा है।
- प्रारम्भिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण को अधिक रोचक एवं बोधगम्य बनाने के उद्देश्य से संस्कृत ई लर्निंग कन्टेन्ट का निर्माण ऑडियो सी.डी. के रूप में किया गया है।
- पाठ्यपुस्तकों को डिजिटल वर्ड से जोड़ने हेतु कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्यपुस्तकों में Q.R कोड लगाने का कार्य किया गया है।

राज्य में संचालित संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष एवं उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष की परिषदीय परीक्षा में राज्य स्तरीय सम्पूर्ण पाठ्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त 10–10 छात्र/छात्राओं को क्रमशः पाँच सौ रुपये एवं एक हजार रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है।

- संस्कृत अकादमी द्वारा संस्कृत के प्रचार–प्रसार के दृष्टिगत् राज्य के 46 संस्कृत महाविद्यालयों के पुस्तकालय हेतु संस्कृत पाठयक्रमों की शास्त्री एवं आचार्य की पुस्तकों का वितरण किया गया है।
- संस्कृत के प्रचार–प्रसार हेतु संस्कृत अकादमी हरिद्वार परिसर में संस्कृत चैनल की स्थापना की कार्यवाही गतिमान है।
- राज्य में संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊँ मण्डल में एक–एक राजकीय आदर्श आवासीय संस्कृत विद्यालय प्रवेशिका से उत्तर मध्यमा कक्षा एक से 12 तक खोला जाना प्रस्तावित है।
- संस्कृत विद्यालयों में कम्प्यूटर विषय/शिक्षा का प्राविधान किया जाना प्रस्तावित है।
- संस्कृत विद्यालयों में योग एवं शारीरिक शिक्षा को प्रारम्भ से 12वीं तक अनिवार्य किया जाना प्रस्तावित है।

मेरी सरकार द्वारा ई–लर्निंग सेन्टरों से दूरस्थ पॉलिटेक्निक संस्थाओं में विषय विशेषज्ञों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

- तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के अन्य प्रदेशों में पलायन में काफी कमी आयी है। विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षा के साथ–साथ वैश्विक मांग के अनुरूप रोजगारपरक व्यावसायिक शिक्षा के अतिरिक्त शोधपरक शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य भी कर रहा है।
- आई0आई0टी0 / एन0आई0टी0 / आई0आई0एम0 संस्थानों में चयनित उत्तराखण्ड राज्य के मेधावी छात्रों को पाँच हजार प्रति छात्र प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जा रही है। जिसमें सैंतालिस लाख रु0 वितरित किये जा चुके हैं।

मेरी सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को राज्याधीन समूह 'ग' एंव 'घ' की सेवाओं में रोजगार दिये जाने की व्यवस्था की है।

- वीरता पदक विजेताओं को शासन द्वारा देय एक मुश्त एवं वार्षिकी में अभूतपूर्व वृद्धि की है तथा वार्षिकी जो पूर्व में 30 वर्षों तक के लिए अनुमन्य थी, उसे आजीवन कर दिया गया है। आज राज्य देश का सबसे अधिक अनुदान देने वाले राज्यों में से एक है।
- द्वितीय विश्व युद्ध के नान पेंशनर व विधवाओं को प्रतिमाह आठ हजार रूपये पेंशन / अनुदान का भुगतान किया जा रहा है। इससे इनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है।
- विभिन्न युद्धों व सीमान्त झड़पों तथा आन्तरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों / अर्द्धसैनिक बलों की विधवाओं / आश्रितों को एक मुश्त अनुग्रह अनुदान हेतु दस लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है।
- सैनिकों के आश्रितों को निशुल्क सेना एंव पुलिस बल में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। देहरादून तथा ऊधमसिंहनगर में भर्ती प्रशिक्षण दिये जाने हेतु प्रत्येक दो माह में कैम्प लगायें गये हैं एवं आवास, भोजन व प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था की गयी है।
- वर्तमान में राज्य में 33 सैनिक विश्राम गृह संचालित है। 3 सैनिक विश्राम गृह निर्माणाधीन हैं। भूतपूर्व सैनिक, सेवारत सैनिकों एवं उनके परिवारों द्वारा सैनिक विश्राम गृहों का विधिवत् प्रयोग किया जा रहा है।
- राज्य के सेवानिवृत सैन्य अधिकारियों, सैन्य कार्मिकों, पूर्व सैनिकों को गृह कर में छूट दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

मेरी सरकार कार्मिक प्रबन्धन एवं सतर्कता के दृष्टिगत सेवा सम्बन्धी मामलों में नीति निर्धारण, परामर्श सम्बन्धी कार्य तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का कार्य त्वरित गति से कर रही है।

- जीरो टालरेन्स नीति के तहत सतर्कता अभियान चलाकर कतिपय प्रकरणों में कार्मिकों को रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की गयी है।
- निष्पक्षता, पारदर्शिता और दक्षता के मानकों के अनुरूप सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों में रिक्त पदों के सापेक्ष 1272 अभ्यर्थियों की चयन संस्तुति लोक सेवा आयोग से शासन को प्राप्त हो चुकी है। 983 पदों के सापेक्ष साक्षात्कार आयोजित किये गये हैं।
- अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वर्तमान तक 5350 पदों के सापेक्ष 802 पदों की विज्ञप्तियां जारी की गयी हैं, तथा 1050 पदों की विज्ञप्ति प्रकाशन की प्रक्रिया गतिमान है।

मेरी सरकार राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए विगत 2 वर्षो से खेल महाकुंभ का आयोजन कर राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक खेलों को एवं प्रतिभावान खिलाडियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिये जाने हेतु वचनबद्ध है।

- भारतीय ओलम्पिक संघ के 38 वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु प्रमुख आयोजन स्थलों के निर्माण कार्य सहित अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है।
- राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने हेतु सुप्रसिद्ध विदेशी प्रशिक्षकों को अनुबन्धित किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।
- राज्य के उदीयमान खिलाड़ी जिनके द्वारा राज्य की ओर से प्रतिभाग कर राज्य का नाम रोशन किया गया ऐसे 26 अन्तर्राष्ट्रीय एवं 22 राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों एवं उनके प्रशिक्षकों को रू0 52.51 लाख की धनराशि स्वीकृत कर पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गयी है।

मेरी सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन के विकास हेतु जनपद पौड़ी में झलपाली से दीवाडाडा रसल्वाण, कीर्तिखाल से भैरवगढ़ी मन्दिर तथा ऋषिकेश (स्वर्गाश्रम) से नीलकंठ मन्दिर रोप वे निर्माण हेतु फिजिबिलिटी स्टडी की जा रही है।

- चारधाम यात्रा 2020 में आने वाले यात्रियों की सुविधा हेतु 131 जनसुविधाओं के नवीनीकरण व उच्चीकरण की कार्यवाही गतिमान है।

- प्रदेश में मुख्य रूप से ग्रामीण व पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन रोकने के उददेश्य से "दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना" प्रारम्भ की गयी है, इसके अन्तर्गत अब तक 1946 होम स्टे का पंजीकरण किया गया है।
- "श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट" की स्थापना की गयी है। श्री केदारनाथ धाम के सुनियोजित विकास के अन्तर्गत अधिकांश कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं।
- नीति आयोग के माध्यम से ऋषिकेश में आई0डी0पी0एल0 में कन्वेंशन सेन्टर की स्थापना हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु चयन किया गया है।
- "सुरकण्डा देवी" एवं "पूर्णागिरी देवी" रोप वे परियोजनाओं का निर्माण कार्य गतिमान है।
- देहरादून से मसूरी तक रोप वे पी0पी0पी0 मोड में विकसित किये जाने हेतु निजी निवेशक का चयन किया गया है। केदारनाथ, नैनीताल व अन्य स्थलों पर रोप वे विकसित किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न चरणों में कार्यवाही गतिमान है।
- यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली के अन्तर्गत सभी पर्यटन इकाइयों की ऑनलाइन पंजीकरण व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है।
- वित्तीय वर्ष में राज्य को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार सहित अन्य क्षेत्रों में भी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

मेरी सरकार द्वारा बालकों का लैंगिंग अपराधों से संरक्षण, हेतु लम्बित प्रकरणों को त्वरित निस्तारण हेतु देहरादून, हरिद्वार, रुड़की एवं ऊधमसिंह नगर में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (Fast Track Special Court) की स्थापना कर दी गयी है।

- वादों के त्वरित निस्तारण हेतु कर्णप्रयाग में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना कर दी गयी है।

मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के प्रमुख नगरों के निकटवर्ती ऐसे ग्रामीण बस्तियों जिनका तेजी से शहरीकरण हो रहा है, में नगरीय क्षेत्र के मानकानुसार पेयजल की सुविधा सुलभ कराने हेतु विश्व बैंक सहायतित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 नौ सौ पचहत्तर करोड़ स्वीकृत कर उसका क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है।

- स्वच्छ पेयजल को सुलभ कराने की दृष्टि से अधिक समस्याग्रस्त अड़तीस ऐसे दूरस्थ नगरों को मानकानुसार पेयजल सुलभ कराने हेतु रु0 एक हजार दो सौ अट्ठावन करोड़ लागत की एक बाह्य सहायतित परियोजना की भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। चयनित वित्तीय संस्था के साथ ऋण अनुबन्ध की कार्यवाही गतिमान है।

- प्रदेश के प्राकृतिक जल स्रोतों के स्राव तथा भूजल के स्तर में हो रही गिरावट के दृष्टिगत जल संरक्षण एवं स्रोत संवर्द्धन का कार्य प्रगति पर है।
- केन्द्र पोषित 'नमामि गंगे परियोजना' के अन्तर्गत गंगा नदी के तट पर स्थित पन्द्रह प्राथमिकता के नगरों में नालों को टैप करने, सीवर एवं गंदे पानी के परिशोधन हेतु आवश्यक क्षमता में मलजल उपचार संयंत्र (STP) के निर्माण का कार्य गतिमान है।
- गंगा नदी पर स्थित प्रमुख नगरों से गंगा नदी में गिरने वाले नालों अथवा सीवर के गंदे पानी के प्रवाह को पूर्णतः निरूद्ध करने और एस.टी.पी. के माध्यम से परिशोधन कर परिशोधित अपशिष्ट जल का प्रवाह गंगा नदी में किये जाने का कार्य प्रगति पर है।
- विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरों हरिद्वार एवं ऋषिकेश को तथा उनके समीपवर्ती अन्य बस्तियों को आन्तरिक सीवर प्रणाली से पूर्णतः संतृप्त करने हेतु इण्डो जर्मन द्विपक्षीय सहयोग (Indo-German Bilateral Co-operation) से रु0 पन्द्रह सौ करोड़ की लागत से 'हरिद्वार–ऋषिकेश सीवर परियोजना' का कार्य गतिमान है।
- कोसी नदी एवं रिस्पना नदी में हो रहे प्रदूषित जल प्रवाह को रोकने हेतु रामनगर में बावन करोड़ की तथा देहरादून में साठ करोड़ रु0 लागत की दो परियोजनाओं की स्वीकृति 'नमामि गंगे परियोजना' के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त करने की कार्यवाही गतिमान है।
- कोसी नदी (रामनगर) परियोजना का कार्य प्रारम्भ किया गया है तथा रिस्पना नदी (देहरादून) से सम्बन्धित परियोजना की निविदा प्रक्रिया गतिमान है।

मेरी सरकार जलागम प्रबन्ध के दृष्टिगत संसाधनों यथा भूमि, जल एवं वनस्पति का संवर्धन, संरक्षण तथा सुनियोजित प्रबन्धन कर योजनाएं ग्राम पंचायतों के माध्यम से सामुदायिक सहयोग से चलाये जाने का कार्य कर रही है।

- कृषि विविधीकरण के साथ ही कृषकों के आय में वृद्धि हेतु कृषि उत्पादों के मूल्य सवंर्धन व वितरण के लिए ग्रोथ सैन्टर की स्थापना की गयी है।
- वाह्य वित्त पोषित रु0 एक हजार तीन सौ करोड़ व केन्द्र पोषित रु0 एक सौ पचास करोड़ लागत की जलागम विकास योजनाओं से प्रदेश में एक सौ एक्यावन सूक्ष्म जलागमों के चार हजार तीन सौ तैंतालिस वर्ग कि0मी0 क्षेत्र में परियोजना कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कराया जा रहा है।
- परियोजना कार्यक्रमों से 31 विकास खण्डों के 978 ग्राम पंचायतों के एक हजार नौ सौ तीन राजस्व ग्राम लाभान्वित हो रहे हैं।

- जलागम विकास योजनाओं" का निर्माण तथा उनका कार्यान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है। कार्यान्वित योजनाओं के अन्तर्गत अब तक रू0 आठ सौ सैंतालिस करोड़ व्यय किया गया है।
- संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के वित्त पोषण से पौड़ी गढ़वाल में 5.93 मिलियन अमेरिकन डालर लागत की जैफ-6 ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना का कार्यान्वयन इसी वित्तीय वर्ष से किया जाना प्रस्तावित है।

सिंचाई सुविधाओं में आधुनिक एवं अभिनव तकनीकों का प्रयोग प्रारम्भ किया गया है एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के क्रम में नलकूप एवं लघुडाल निर्माण की योजनाओं में सूक्ष्म सिंचन प्रणाली यथा स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई किये जाने को प्राथमिकता दी जा रही है।

- जल संसाधनों के नियोजन, विकास एवं प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय जल नीति के सिद्धान्तों के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य जल नीति, 2019 प्रख्यापित की गई है।
- गोला नदी पर बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु आवश्यक स्वीकृतियां पूर्ण कर ली गई है। परियोजना को वाह्य सहायतित योजनान्तर्गत वित्त पोषण हेतु भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।
- देहरादून एवं उपनगरीय क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए सौंग नदी पर सौंग पेयजल बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। अपेक्षित स्वीकृतियों, पुनर्वास एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्यवाही गतिमान है।
- ऊधमसिंहनगर में हरिपुरा बौर एवं तुमरिया जलाशय पर सेकी (SECI) भारत सरकार द्वारा 200 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पी0वी0 तथा राज्य सरकार की ओर से 40 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाये जाने की कार्यवाही गतिमान है।
- राज्य में प्राकृतिक स्त्रोतों के पुनर्जीविकरण कर वर्षा जल का संचयन कर पेयजल एवं सिंचाई को बढ़ावा देने हेतु जलाशयों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें सूर्यधार जलाशय देहरादून, गंगास जलाशय अल्मोड़ा, थरकोट बैराज पिथौरागढ़, कोलीढेक चम्पावत प्रमुख हैं।
- देहरादून की रिस्पना एवं बिन्दाल नदी एवं नैनीताल की नैनीझील के पुनर्जीविकरण की कार्यवाही गतिमान है।

मेरी सरकार लघु सिचाई योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष में राज्य योजनान्तर्गत सोलह करोड़ सत्तर लाख एवं केन्द्रपोषित योजनान्तर्गत रू0 चौरासी करोड़ कुल रू0 एक अरब सत्तर लाख का बजट स्वीकृत किया गया है।

- लघु सिंचाई कार्यक्रमों के अन्तर्गत दो सौ पचहत्तर सिंचाई हौज, एक सौ चौहत्तर किलोमीटर सिंचाई गूल, तीस आर्टीजन कूप, दो हाईड्रम तथा एक सौ पचासी पम्पसैट का निर्माण कर चार हजार एक सौ बहत्तर हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।
- भारत सरकार द्वारा स्वीकृत केन्द्रपोषित योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में एक सौ सत्तासी सिंचाई हौज, छियालिस हजार सात सौ छियालिस मीटर पाईपलाईन तथा एक सौ छियालिस कि0मी0 सिंचाई गूल का निर्माण कर तीन हजार छः सौ एकहत्तर हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।
- नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित योजना के अन्तर्गत ऊधमसिंह नगर में रू0 सात करोड़ सड़सठ लाख का व्यय करते हुए 48 आर्टीजन कूपों का निर्माण कर 492 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।
- भारत सरकार द्वारा शत–प्रतिशत वित्तपोषण से प्रति पाँच वर्ष के अन्तराल पर लघु सिंचाई कार्यों की संगणना के अन्तर्गत पाँचवी लघु सिंचाई संगणन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, एवं छठवीं संगणना का कार्य गतिमान है।

मेरी सरकार प्रदेश की भौगोलिक एवं जलवायु स्थिति तथा स्थानीय आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुये राज्य कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

- वित्तीय वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन में उत्कृष्ठ प्रदर्शन हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित कर पाँच करोड़ नगद धनराशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है।
- वित्तीय वर्ष में प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन 18.78 लाख मैट्रिक टन हुआ है।
- भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन एवं प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत जल संरक्षण तथा जल संचय संरचनाओं के निर्माण पर कार्य किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में अठारह विभागों की छाछठ परियोजनायें संचालित की गयी हैं जिसमें से उन्तीस परियोजनायें पूर्ण हो चुकी हैं।
- प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि (पी0एम0 किसान) पात्रता के अन्तर्गत 8.38 लाख लाभार्थियों में से 6.87 लाख कृषकों को लाभान्वित करते हुए 480.45 करोड़ की धनराशि का वितरण किया गया है।

- प्रधानमन्त्री किसान मानधन योजना (PMKMY) में 18 से 40 वर्ष तक के सभी भू–धारक लघु एवं सीमान्त किसानों के लिये सामाजिक सुरक्षा कवच सृजित करने के उद्देश्य से वृद्धावस्था पेशन हेतु कृषकों को पंजीकृत किया जा रहा है।
- वर्षा आधारित क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं जल संचय बढ़ाने के लिये भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन एवं प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत जल संरक्षण तथा जल संचय संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है।
- संचित जल एवं भूमिगत जल से सिंचन क्षेत्रफल बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत टपक एवं फव्वारा सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। सिंचाई जल के ह्रास को रोकने के लिये नहर/नालियों के स्थान पर एच0डी0पी0ई0 पाईपों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- कृषि के उत्थान एवं कृषि कार्यक्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति योजना लागू की गयी है।
- 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में शीतोष्ण फलों का वृक्षारोपण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त सब्जी/औषधीय एवं संगध पादप, पुष्पोत्पादन प्रक्षेत्र के अन्तर्गत भी लगभग 15 हैक्टेयर क्षेत्रफल विकसित किया जा रहा है।
- विश्वविद्यालय में आई.सी.ए.आर. द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता से 02 कृषि विज्ञान केन्द्र संचालित है। विश्वविद्यालय कैम्पस को "हरित परिसर" (Green Campus) की तरह विकसित करने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा स्ट्रीट लाईट्स का प्रयोग किया जा रहा हैं।

मेरी सरकार ने ओवर स्पीडिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने हेतु व्यवसायिक वाहनों में (Speed Limiting Device) को लगाना अनिवार्य कर दिया है तथा 84 हजार पुराने वाहनों में गति नियंत्रक उपकरण संयोजित कर दिये गये हैं।

- स्मार्ट कार्ड आधारित चालक लाइसेन्स एवं पंजीयन प्रमाण पत्रों में क्यू0आर0 कोड आधारित स्मार्ट कार्ड जारी किये गये हैं।
- सार्वजनिक सेवा भाव से होने वाली दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता दो गुना करते हुए मृतक आश्रित को एक लाख रूपये एवं घायल व्यक्तियों को चालीस हजार रूपये एंव सामान्य रूप से घायल व्यक्ति को दस हजार रूपये की आर्थिक राहत राशि दी जा रही है।
- पोल्यूसन टैस्टिंग सेन्टरों को वाहन डाटा बेस से जोड़े जाने की कार्यवाही गतिमान है।
- निगम की कुल आय में विगत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि हुई है।

राज्य की जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति विभिन्न प्रकार के औद्यानिक फसलों (फल, सब्जी, मसाला, पुष्प, मशरूम तथा मौनपालन) के उत्पादन हेतु अनुकूल है। मेरी सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इन फसलों के विकास हेतु व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं।

- राज्य में स्थापित सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों एवं प्रशिक्षण केन्द्र पर लगभग 927 कुन्तल फल एवं सब्जी प्रसंस्करण किया गया है। तथा तीन हजार सात सौ बहत्तर व्यक्तियों को इस विषय में प्रशिक्षित किया गया है।
- कृषकों के फलों का उचित मूल्य दिलाये जाने हेतु 50 प्रतिशत राजसहायता पर 1.83 लाख कोरोगेटेड बॉक्स, 4,777 प्लास्टिक क्रेट्स का वितरण किया गया है। राज्य के निर्माण के बाद प्रथम बार सेब उत्पादकों को जिला योजनान्तर्गत अतिरिक्त राज्य सैक्टर में बजट प्राविधानित कर 1.83 लाख कोरोगेटेड बॉक्स(पेटियाँ) 50 प्रतिशत राजसहायता के साथ प्रदान किये गये हैं।
- राजकीय प्रक्षेत्रों में विभिन्न फल प्रजातियों के 4.00 लाख फल पौधों का उत्पादन 115 कुन्तल उन्नत किस्म के सब्जी बीजों का उत्पादन किया गया है।
- मौनपालन को बढ़ावा देने हेतु कृषकों को तीन हजार छः सौ बॉक्सों का परम्परागत वितरण कर एक सौ साठ मौनगृह, मौनवंश वितरित किये गये हैं।
- भारत सरकार के दिशा निर्देशन में प्रदेश में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ (फसल–आलू, अदरक, टमाटर, मिर्च एवं फ्रैंचबीन) एवं रबी मौसम (सेब, आडू, माल्टा, संतरा, मौसम्बी, आम, लीची, आलू, टमाटर एवं मटर) हेतु संचालित है, जिसके अन्तर्गत रबी एवं खरीफ फसलों हेतु क्रमशः तेरह हजार एक सौ एवं अड़तालिस हजार एक सौ बारह कृषकों की फसलों का बीमा किया गया।
- कृषकों को पॉलीहाउस में खेती करने हेतु 100 से 500 वर्ग मीटर तक पॉलीहाउस निर्माण हेतु (50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 30 प्रतिशत राज्यांश) 80 प्रतिशत राजसहायता अधिकतम रू0 365.70 प्रति वर्ग मीटर की दर से दी जा रही है तथा इसके अतिरिक्त 5,400 वर्गमीटर क्षेत्र में पॉलीहाउस स्थापित किये गये हैं।
- राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु वर्मी कम्पोस्ट इकाइयों की स्थापना से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं, महिलाओं तथा स्वयं सहायता समूहों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रू0 तेतीस हजार तीन सौ प्रति इकाई की लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम एक इकाई हेतु राजसहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष में 112 वर्मी कम्पोस्टों का निर्माण कराया गया है।
- बागवानी मिशन योजनान्तर्गत कृषकों को 25 से 55 प्रतिशत तक विभिन्न घटकों में बागवानी विकास हेतु सहायता प्रदान की गयी हैं। वित्तीय वर्ष में बागवानी विकास के

विभिन्न घटकों यथा फल, क्षेत्रफल विस्तार के अन्तर्गत 832 है0, सब्जी क्षेत्रफल विस्तार हेतु 775 हैक्टेयर, मसाला क्षेत्रफल विस्तार हेतु 150 हैक्टेयर व पुष्प क्षेत्रफल विस्तार के अन्तर्गत 40 हैक्टेयर क्षेत्रफल आच्छादित किया गया है। इसके साथ ही 3.00 लाख वर्गमीटर में एन्टी हेलनेट की स्थापना कर, सहायता प्रदान की गयी है।

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत पर ड्रॉप मोर क्राप (per drop more crop) के अन्तर्गत कृषकों को ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली स्थापित करने हेतु 45 से 55 प्रतिशत तक राजसहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष में 2813 है0 में ड्रिप, 3909 हैक्टेयर में स्प्रिंकलर प्रणाली की स्थापना कर 8178 कृषकों को लाभान्वित किया गया है।
- परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 1241 क्लस्टरों का चयन किया गया है, जिसमें 24820 हैक्टेयर क्षेत्र आच्छादित करते हुए 57992 कास्तकारों को लाभान्वित किया गया है।
- वित्तीय वर्ष में छः हजार एक सौ पचासी व्यक्तियों से 239 मैट्रिक टन कोया उत्पादन, 17 सहकारी समितियों को लाभान्वित कर 3000 मीटर वस्त्र उत्पादन, तीस मैट्रिक टन धागा उत्पादन किया गया है। साथ ही रेशम उत्पादकों को मानसून फसल के प्रोत्साहन हेतु 68 मैट्रिक टन कोये पर धनराशि वितरित की गयी है।

मैंने अपनी सरकार की विगत एक वर्ष में किये गये विभिन्न विकास के कार्यों का संक्षिप्त विवरण के साथ–साथ आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की प्राथमिकताओं का संक्षिप्त विवरण आपके समक्ष रखा है। सरकार अपने संकल्प पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार की प्राथमिकता राज्य में विकेन्द्रीकृत विकास करना एवं सबको साथ लेकर राज्य को विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाना है। इस महत्वपूर्ण संकल्प को पूर्ण करने के लिए आपके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी महानुभावों को आगामी वित्तीय वर्ष हेतु वित्तीय व विधायी कार्यों में सक्रिय व सकारात्मक भागीदारी के लिए शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ।

धन्यवाद!

–जय हिन्द–